तापमान

भोपाल	24.0°	28.0°
इंदौर	23.0°	29.0°
जबलपुर	24.0°	27.0°
ग्वालियर	26.0°	33.0°
सागर	22.0°	27.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 262, पृष्ठ 12)
श्रावण, शुक्ल नवमी संवत् 2083
शुक्रवार, 21 अगस्त 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naidunialive.com | भोपाल संस्करण | भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... पीथमपुर में 850 करोड़ के निवेश से शुरू हुईं दो ...

खेल... भारत की उन्नति बीडब्ल्यूएफ विश्व चैम्पियनशिप से ...

व्यापार... महँगाई नियंत्रित रखना हो सरकार का मुख्य...

देश-विदेश... देश के कई राज्यों में बारिश का कहर, बाढ़ के ...

खास-खबरें

स्कूल में 6 वर्षीय बच्चे की हार्टअटैक से मौत

नईदुनिया ब्यूरो, विशाखापट्टनमः विशाखापट्टनम में गुरुवार को शिक्षक की पिटाई के बाद छह वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। कक्षा में लगे सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड हुई। फुटेज में पिटाई के बाद बच्चा शिक्षक की गोद में गिरता दिखाई दे रहा है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक की पिटाई से बच्चा दहशत में आ गया और उसे हृदयाघात हो गया। मृतक प्रणय तेजा लिटिल गार्डन्स स्कूल में यूकेजी का छात्र था। बताया गया कि शिक्षक ने उसके कपड़े उतारने की कोशिश की और दो बार थप्पड़ मारे। शिक्षक की गोद में गिरने के बाद बच्चे को किंग जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का निधन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः तिहाड़ जेल में बंद पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सूत्रों के अनुसार, उन्हें मृत अवस्था में सफदरजंग अस्पताल लाया गया। सज्जन कुमार दिसंबर 2018 से जेल में बंद थे और करीब सात वर्ष आठ महीने से सजा काट रहे थे। उन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े दो मामलों में उम्रकैद की सजा मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को पांच सिखों की हत्या के मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

पूर्व न्यायाधीश, पुलिस-सीबीआई के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल

‘सुप्रीम पंच-परमेश्वर’ करेंगे जंतर-मंतर मामले की जाँच, सुको ने बनाई समिति

आर. सुभाष रेड्डी
पूर्व न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट

रवि शंकर झा
पूर्व मुख्य न्यायाधीश

शलिंदर कौर
पूर्व न्यायाधीश

ऋषि कुमार शुक्ला
पूर्व निदेशक सीबीआई

डॉ. एलआर बिश्नोई
सेवानिवृत्त डीजीपी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः जंतर-मंतर मामले की जाँच अब ‘सुप्रीम पंच-परमेश्वर’ करेंगे। सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। समिति में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शलिंदर कौर, केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डॉ. एलआर बिश्नोई को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करने का फैसला लिया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कार्रवाई के दौरान पैलेटगन के इस्तेमाल और महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगाए थे।

भ्रूण लिंग परीक्षण मामलों की जांच पुलिस नहीं करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े पीसीपीएनडीटी कानून के मामलों की जांच पुलिस नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में कानून के तहत नियुक्त अधिकारी ही कार्रवाई करेंगे। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पीसीपीएनडीटी कानून से जुड़े मामले तकनीकी और चिकित्सा जानकारी से संबंधित होते हैं। पुलिस इस कानून के तहत सीधे प्राथमिकी दर्ज कर डॉक्टरों या अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस की भूमिका केवल अधिकृत अधिकारियों को सहायता देने तक सीमित रहेगी। यह व्यवस्था केवल पीसीपीएनडीटी कानून के तहत आने वाले अपराधों पर लागू होगी।

36 दिन चला था प्रदर्शन

जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन हुआ था। यह प्रदर्शन 36 दिन तक चला था और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच समाप्त हुआ था। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। इसमें पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के घायल होने की बात सामने आई थी। प्रदर्शन के दौरान 120 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी भी दी गई थी।

संसद मार्च को बताया गैरकानूनी

दिल्ली पुलिस ने 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैरकानूनी था और इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन में कई हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हो गए थे। पुलिस ने अदालत को बताया था कि संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। पुलिस के अनुसार, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त सचिन शर्मा ने इस संबंध में हलफनामा पुलिस कार्रवाई की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं के जवाब में पेश किया था।

किसानों को दिन में पर्याप्त बिजली मिलेगीः डॉ. यादव

▶▶ नई तकनीक से खेती में समृद्धि के रास्ते खुले, फसल विविधीकरण, उद्यानिकी और पशुपालन से जुड़ें किसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नई तकनीक और नवाचार ने खेती में समृद्धि के नए रास्ते खोले हैं। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ फसल विविधीकरण, उद्यानिकी और पशुपालन से जुड़ना चाहिए। फसल उत्पादन के साथ दुग्ध उत्पादन और मछली पालन अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अशोकनगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अशोकनगर के किसान अपनी मेहनत से प्रदेश के किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। जिले के शरबती गेहूं की देशभर में मांग है। किसानों में धनिया और गुलाब जैसी उद्यानिकी फसलों के प्रति रुचि बढ़ रही है। कम बारिश की चुनौती के बीच डीआरएस तकनीक से धान की रोपाई का रकबा बढ़ाया गया है। फसल विविधीकरण के कारण चना और मसूर का रकबा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि किसान, महिला, गरीब और युवा राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीमा पर जवान और खेत में किसान की भूमिका समान है। किसान कल्याण वर्ष के दौरान सरकार किसान हित में सक्रियता से कार्य कर रही है। खेती को लाभप्रद बनाने के लिए बिजली, पानी और खेतों तक सड़क संपर्क की व्यवस्था पर काम जारी है। कृषि भूमि के भू-अर्जन पर किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कुछ माह बाद किसानों को दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सिंचाई के लिए किसानों को पांच, सात और 10 हार्सपावर के बिजली पंपों पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों की आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों को जन्माष्टमी, बलराम जयंती और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दीं।

कक्षा 11वीं-12वीं की राजनीति विज्ञान की नई किताबें बनेंगी

▶▶ 20 सदस्यीय टीम का पुनर्गठन, भारतीय ज्ञान और संस्कृति से जुड़े विषयों पर रहेगा जोर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 11वीं और 12वीं की राजनीति विज्ञान की नई किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय पाठ्यपुस्तक विकास टीम का पुनर्गठन किया है। नई टीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करेगी। प्रो. संदीप शास्त्री को टीम का प्रमुख बनाया गया है, जबकि डॉ. वंथांगपुई खोबुंग और डॉ. सुभाष सिंह समन्वयक होंगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टीम के कम से कम चार सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उससे जुड़े संगठनों से संबंध रहे हैं। इनमें यदुनाथ देशपांडे, डॉ. प्रशांत दिवेकर, प्रो. वंदना मिश्रा और डॉ. रवि रमेशचंद्र शुक्ला शामिल हैं। एनसीईआरटी ने कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की किताब 30 नवंबर 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जबकि कक्षा 12वीं की किताब 30 जुलाई 2027 तक तैयार की जानी है। टीम में विश्वविद्यालयों, विधि संस्थानों, मुक्त शिक्षा संस्थानों और सरकारी संस्थाओं के शिक्षाविद, शिक्षक तथा विशेषज्ञ शामिल हैं। नई किताबों में भारतीय ज्ञान प्रणाली और संस्कृति से जुड़े विषयों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा समानता, समावेशन, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण और तकनीक से जुड़े विषयों को भी शामिल किया जाएगा। किताबें तैयार करने के लिए एनसीईआरटी के विशेषज्ञों से भी सलाह ली जाएगी।

झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने पर हाईकोर्ट की रोक

नईदुनिया ब्यूरो, रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा। अदालत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने वाले आदेश पर भी रोक लगा दी है।

राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के चलते 17 अगस्त को 22 परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। इनमें 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा शामिल थीं। मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गई है।

इन परीक्षाओं के आधार पर विभिन्न विभागों में 2394 अधिकारी कार्यरत थे। नियुक्तियां रद्द होने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के सफल

कटघरे में सरकार...

राज्य सरकार को 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश

अभ्यर्थियों को नौकरी से हटना पड़ा। इसके विरोध में अधिकारियों ने गुरुवार शाम बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली और नियुक्तियां रद्द करने का फैसला वापस लेने की मांग की। परीक्षाएं रद्द होने के विरोध में अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 26 दिनों तक चले आंदोलन के बाद छात्रों ने सरकार के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखीं और 60 दिनों के लिए धरना स्थगित किया है। छात्रों ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने, विधानसभा घेराव के दौरान दर्ज मामले वापस लेने और परीक्षा सुधार संबंधी समिति में छात्र प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है। छात्रों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातकोत्तर शिक्षक, नगर पालिका, माध्यमिक आचार्य, प्रयोगशाला सहायक और आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षाएं भी रद्द कर नए सिरे से कराने की मांग की है। साथ ही अपराध अनुसंधान विभाग की जांच के मामले में सरकार से अदालत में मजबूती से पक्ष रखने को कहा है। 25 जुलाई से शुरू हुआ जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन 19 अगस्त को फिलहाल दो महीने के लिए स्थगित किया गया। तीन छात्रों का अनशन पद्मश्री मधु मंसूरी और कोतवाली निरीक्षक सनोज कुमार चौधरी ने जूस पिलाकर समाप्त कराया।

भारत आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत में 12 और 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी भारत आने की तैयारियां चल रही हैं। यदि जिनपिंग भारत आते हैं तो यह करीब सात साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 में भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, चीन की ओर से जिनपिंग के दौरे की अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों देशों की अग्रिम टीमों के दौरे की तैयारियां चल रही हैं।

पूरा वंदे मातरम नहीं गाना देश विरोधीः अमित शाह

नईदुनिया ब्यूरो, चेन्नईः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस पर वंदे मातरम को पूरा नहीं गाने के फैसले को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रगीत के केवल शुरुआती दो पद गाने का फैसला हैरान करने वाला और देशविरोधी है। शाह ने आरोप लगाया कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटकर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था, जिससे दो-राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1937 के फैसले को सुधारा है। उन्होंने कांग्रेस के फैसले को तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति बताया और कहा कि देश में अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच और संसद तथा विधानसभा में उठाएगी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहा है और कांग्रेस के लिए यह भावनात्मक विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कांग्रेस कार्यसमिति ने बुधवार को फैसला किया था कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के छह में से केवल शुरुआती दो पद गाए जाएंगे। यह निर्णय 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में हुए विवाद के बाद लिया गया।

भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन पर बैठक

नईदुनिया ब्यूरो, देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर 14वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक शुरू हो गई है। मसूरी रोड स्थित एक निजी होटल में दो दिन तक चलने वाली बैठक में चार दौर की वार्ता होगी। इसमें सीमा विवाद, सीमा निर्धारण, सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सर्वे ऑफ इंडिया के ब्रिटिश शासनकालीन नक्शों और पुराने अभिलेखों के आधार पर भारत-नेपाल के बीच सीमा विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। दोनों देशों के अधिकारी पुराने दस्तावेजों का मौजूदा भौगोलिक स्थिति से मिलान कर विवादित सीमा क्षेत्रों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफ्ले कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सेना और सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी भी शामिल हैं।

बैठक का प्रमुख मुद्दा भारत-नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद का समाधान रहेगा। अधिकारियों द्वारा ब्रिटिशकालीन नक्शों के साथ उपलब्ध अन्य दस्तावेजों और वर्तमान स्थिति का भी अध्ययन किया जाएगा।

दिल्ली में पाक हाई कमीशन के बाहर चला बुलडोजर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचों को बुधवार देर रात बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, ये ढांचे हाई कमीशन की निर्धारित सीमा से बाहर बनाए गए थे। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित शांतिपथ पर है। कार्रवाई के दौरान बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार प्रबंधन के लिए बनाए गए ढांचे भी हटाए गए। संबंधित एजेंसियों ने जेसीबी की मदद से यह कार्रवाई की।

आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने

विपक्षी उम्मीदवार को 167 वोटों से हराया, 35 साल बाद चुनाव

ढाका, एजेंसीः बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें संसद में 255 वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को 88 वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को संसद भवन में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक मतदान हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू की गई और परिणाम घोषित कर दिया गया। चुनाव में कुल 349 सांसदों ने मतदान किया। बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे नहीं करती, बल्कि संसद सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संसद में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पास दो-तिहाई बहुमत होने के कारण आलमगीर की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। आलमगीर के सामने जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन के समर्थन वाले एलडीपी उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद थे।

वोट की आजादी नहीं :ओली

बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद 11 दलों के गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (रिटायर्ड) ओली अहमद ने चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव का नतीजा पहले से तय था और बांग्लादेश में लोकतंत्र नियंत्रित है। ढाका में गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए ओली ने कहा कि किसी भी सांसद को अपनी मर्जी से वोट देने की आजादी नहीं है। पार्टी जिस उम्मीदवार को वोट देने को कहती है, सांसद को उसी के पक्ष में वोट देना पड़ता है।

खास खबर *21 मासूमों की मौत ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल, सवालों के घेरे में निगरानी ...*

मलेरिया से ज्यादा घातक प्रशासन की नींद

डॉ. शिशिर उपाध्याय

बालाघाट के बिरसा विकासखंड में 21 मासूमों की मौत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के उन दावों की पोल खोल दी है, जिनमें कागज पर मलेरिया का उन्मूलन हो चुका है और गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच चुकी हैं। जमीन पर तस्वीर कुछ और है। बीमारी गांवों में पैर पसारती रही और जिम्मेदार तंत्र शायद फाइलों में स्वस्थ प्रदेश की तस्वीर देखता रहा।

अब जब मौतों का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर घूम रही हैं, जांच शिविर लग रहे हैं और अधिकारियों की सक्रियता दिखाई दे रही है। लगता है प्रशासन को बीमारी की गंभीरता समझने के लिए पहले मौतों का आंकड़ा चाहिए था। सवाल यह है कि अगर यही तत्परता पहले दिखाई जाती तो शायद कई घरों के चिराग आज भी रोशन होते।

मलेरिया कोई अचानक आई बीमारी नहीं है। इसके लक्षण, फैलाव और रोकथाम के उपाय स्वास्थ्य विभाग को अच्छी तरह मालूम हैं। फिर भी यदि किसी आदिवासी इलाके में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो जाएं और बच्चों की मौतें होने लगें तो यह केवल बीमारी का प्रकोप नहीं, व्यवस्था की निगरानी का भी पोस्टमार्टम है।

विडंबना देखिए, करोड़ों रुपये की स्वास्थ्य योजनाएं चलती हैं, जागरूकता अभियान होते हैं, मच्छरदानी बांटी जाती हैं और हर साल बीमारी रोकने के दावे किए जाते हैं। लेकिन जब गांव में बुखार दस्तक देता है तो अस्पताल दूर, दवा दूर और डॉक्टर भी दूर नजर आते हैं। कागज पर स्वास्थ्य व्यवस्था चौकन्नी रहती है, जमीन पर बीमारी चौकन्नी निकलती है।

मौतों के आंकड़ों को लेकर भी अलग-अलग दावे चिंता बढ़ाते हैं। प्रशासन कम संख्या बता रहा है, जबकि स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि अधिक मौतों की बात कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, पूरी पारदर्शिता दिखानी चाहिए।

अब जांच और अभियान से आगे बढ़कर जवाबदेही तय करनी होगी। आखिर बीमारी फैलने से पहले निगरानी क्यों नहीं हुई? स्वास्थ्य दल समय पर गांवों तक क्यों नहीं पहुंचे? गंभीर मरीजों को उपचार क्यों नहीं मिला? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं।

बालाघाट की त्रासदी यह संदेश दे रही है कि प्रशासन अगर मौतों के बाद ही जागेगा तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बीमारी नहीं, उसकी अपनी सुस्ती होगी।

यूएई में पाक यात्रियों से भेदभाव का आरोप

इस्लामाबाद,एजेंसीः पाकिस्तान के सांसद और नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष असद कैसर ने संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तानी यात्रियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने संसद में कहा कि फ्लाइट रद्द होने के बाद भारतीय और अमेरिकी नागरिकों को होटल में ठहरने की सुविधा दी गई, जबकि पाकिस्तानी यात्रियों को कमरा नहीं मिला।

कैसर ने कहा कि वह खुद इस घटना के दौरान मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से यूएई अधिकारियों के सामने यह मामला उठाने की मांग की। हालांकि, उन्होंने होटल का नाम, यात्रियों की संख्या या कोई प्रमाण साझा नहीं किया।